भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3837
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2019

बीएसएनएल से 4जी स्पेक्ट्रम लागत की वसूली

3837. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से 4जी-स्पेक्ट्रम लागत की वसूली करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक होने की संभावना है;

(ख) देश में 5जी स्पेक्ट्रम की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सरकार बीएसएनएल के माध्यम से 5जी सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, मानव विकास संसाधन तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) मंत्रिमंडल ने दिनांक 23.10.2019 को आयोजित की गई अपनी बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 4जी सेवाएं प्रदान करने हेतु बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक रूप से आवंटन करना शामिल है। स्पेक्ट्रम की कुल कीमत (जीएसटी को छोड़कर) 14,115 करोड़ रुपए का वित्तपोषण सरकार द्वारा पूंजी निवेश के माध्यम से किया जाएगा। स्पेक्ट्रम की कीमत पर जीएसटी घटक के 2,541 करोड़ रुपए का वित्तपोषण भी सरकार से बजटीय आवंटन के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा रेडियो स्पेक्ट्रम और दूरसंचार लाइसेंस प्रौद्यौगिकी तटस्थ है और इनका किसी भी नेटवर्क/सेवाओं के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है। आईएमटी 2020 (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार 2020) जिसे उद्योग जगत में 5जी प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है, के मानकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत में 5जी के विजन को सुस्पष्ट करने तथा इस विजन को साकार करने के लिए नीतिगत पहल तथा कार्य योजनाओं की सिफारिश करने के लिए 5जी इंडिया 2020 हेतु एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयीय फोरम गठित किया गया था। इस उच्च स्तरीय फोरम ने "मेकिंग इण्डिया 5जी रेडी" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार भारत में वहनीय तथा सुरक्षित 5जी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सक्षम फ्रेमवर्क सृजित कर रही है।

(ग) मंत्रिमंडल ने 4जी सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम का आवंटन करने के लिए अपनाए गए सिद्धान्त के आधार पर ही बीएसएनएल को 5जी सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आवंटित करने को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

*****